There is no dearth of funds but the poor are still starving in Kalahandi. They have no land, no money to buy rice. Most of the days they go to sleep hungry and the children cry all night. All the time Kalahandi hits the headlines and successive Governments have introduced scheme after Scheme on povery alleviation. I demand a high level enquiry into the implementation of the KBK,s Long Term Action Plan in Orissa and year-wise report to be laid in the House as per the observations of the special Committee. Thank you.

Impact of Drought-Like Conditions in Rajasthan

श्री ओंकार सिंह लखावत (राजस्थान): माननीय महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख के द्वारा राजस्थान की गम्भीर अकाल स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, इस वर्ष राजस्थान में जो अकाल की स्थिति है - पिछले दो सौ वर्षों में इतना भीषण अकाल वहां कभी नहीं पड़ा। इसको केवल हम अकाल नहीं कह सकते हैं बल्कि इस बार तो यह त्रिकाल है। इस बार स्थिति यह है कि खाने के लिए अनाज पैदा नहीं हुआ है, पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध नहीं है और उसके कारण एक गम्भीर स्थिति यह खड़ी हो गयी है कि लोगों के राजस्थान छोड़कर अन्य राज्यों की ओर पलायन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। हमारा तो सीमांत प्रदेश है और इस कारण से जैसलमेर और बाड़मेर की स्थिति यह बन रही है कि वहां से अधिकांश लोग पलायन करके अन्य राज्यों की ओर जा रहे हैं। इसलिए देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी यह बहुत बड़ा एक खतरा उत्पन्न हो गया है क्योंकि वहां से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है।

गायों की स्थिति यह हो गयी है कि लोगों के पास गायों को खिलाने के लिए चारा नहीं है। पशुओं को पिलाने के लिए पानी नहीं है। कत्लखानों में बेचने की बनिस्बत गायों की सुबह-सुबह पूजा करके उनको तिलक लगाकर जंगल में छोड़ रहे हैं। अधिकांश गाएं और गोवंश कत्लखाने में जाने की स्थिति हो गयी है। उसके कारण पिछले दिनों राज्य में एक झगड़ा हो गया जिसके कारण एक कार्यकर्ता की फलौदी के अंदर हत्या हो गयी । उसके कारण से भी वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में 23 हजार करोड़ रुपया अकाल राहत के ऊपर खर्च हुआ है परंतु हमको एक प्रतिशत भी अकाल का अंतर कम नहीं दिखता। इसलिए मैं भारत सरकार से चाहूंगा कि जब राजस्थान के अधिकांश जिलों

के अंदर अकाल है उस समय उसमें कारगर कदम उठाने की दृष्टि से, अकाल की समस्या से जूझने में राहत प्रदान करने की दृष्टि से, वाटर शेड के मामले में और केंद्रीय राहत के नाते भी - ताकि राज्य की जनता को पलायन नहीं करना पड़े, पशुधन को बचाया जा सके क्योंकि राजस्थान में पशुधन वहां की आर्थिक स्थिति की रीढ़ की हड्डी है - वह पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराए।

महोदय, एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करके अपनी बात को पूरी करना चाहूंगा। बहुत प्रसन्नता के साथ मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि माननीय मोरोपंतजी पिंगले और अन्य जो हमारे यहां पर अंडरग्राउंड वाटर वर्क्स के वैज्ञानिक थे उनके शोध कार्यों के कारण राजस्थान में भूमिगत सरस्वती नदी का पता लग गया है। लगभग 117 किलोमीटर लम्बाई और 70 मीटर गहराई की अंडरग्राउंड सरस्वती नदी जो पहले निरंतर बहती थी और लुप्त हो गयी थी, उस 117 किलोमीटर लम्बी नदी का पता लग गया है। यह नदी लगभग 1700 किलोमीटर लम्बी थी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब अकाल की विभीषिका है तो निश्चित रूप से यदि केन्द्र सरकार राजस्थान सरकार के साथ में किसी तरीके से समन्वय करके इस सरस्वती नदी के ऊपर काम कर सके तो स्थायी रूप से अकाल से हमको मुक्ति मिल सकेगी। ऐसी परिस्थिति में मेरा विनम्र निवेदन है कि आज जब लगभग 42 लाख हेक्टेयर हमारी भूमि बंजर हो रही है, वहां पैदावार बिल्कुल नहीं हो रही है तो इस दृष्टि से भी कुछ काम करने के नाते भी पर्याप्त सहायता राजस्थान को दी जाए तथा इस समन्वय की दृष्टि से, अकाल की दृष्टि से राजस्थान को स्थायी रूप से मुक्ति दिलायी जाए। राजस्थान नहर, जो 75 प्रतिशत हमारे वहां का गेहूं पैदा करती है 1958 में राजस्थान नहर प्रारम्भ हुई थी, अभी तक पैसे के अभाव में पूरी नहीं हो सकी । उसके लिए भी पर्याप्त सहायता प्रदान की जाए, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है । इसलिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के नाते, मैंने यह विशेष उल्लेख इस सदन में किया था । आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कनकमल कटारा (राजस्थान): सभापति महोदय, मैं भी अपने को इस विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करता हूं ।

सदन के नेता (श्री जसवंत सिंह) : माननीय सभापति जी, मैं सरकार की ओर से कहना चाहूंगा और माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को उनकी समुचित व्यवस्था कराने में जो राशि देनी थी वह सब दी जा चुकी है और आपका यह कहना कि केन्द्र यह करे, वह करे, यह मुझे समझ में नहीं

आता कि केन्द्र इससे अधिक क्या करे ? जब-जब राज्य सरकार ने जो मांगा है उनको दिया गया है और यह अकाल की स्थिति में भी राज्य सरकार ने जब-जब केन्द्र से मांगा है उनको समुचित राशि व अन्य सामान दिया गया है ।

श्री ओंकार सिंह लखावत: महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि केन्द्र सरकार ने राजस्थान सरकार को सहायता दी, लेकिन यह काम प्रारम्भ कराने के लिए भी निर्देश प्रदान करायें, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है ।

THE AQUACULTURE AUTHORITY BILL, 2000

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI O. RAJAGOPAL): Sir, I, on behalf of Shri Nitish Kumar, beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of an Aquaculture Authority for regulating the activities connected with aquaculture in the coastal areas and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI O. RAJAGOPAL:Sir, I introduce the Bill.

खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 2000

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : सभापति महोदय, मैं खाद्य निगम अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं ।

The question was put and the motion was adopted.

श्री शांता कुमार : मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं ।

THE SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA (AMENDMENT) BILL, 1999.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA):Sir, I move: